मानभर देवी अग्रवाल

बनाम

राजस्थान राज्य एवं अन्य।

(2016 की सिविल अपील No.11259)

25 नवंबर, 2016

[पिनाकी चंद्र घोस और अशोक भूषण, जे. जे.]

राजस्थान खान और खनिज रियायत नियम, 1986:

धारा 3(2)(xx), 18,48-निर्माण में ठेकेदारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले खनिजों पर 'रॉयल्टी' के भुगतान के लिए सरकारी परिपत्र कार्य-अपीलार्थी, एक ठेकेदार ने खुले बाजार से खरीदे गए खनिजों का उपयोग करके निर्माण कार्य किया-रॉयल्टी से कटौती की गई अपीलार्थी के बिल-अपीलार्थी की याचिका कि रॉयल्टी का भुगतान पट्टेदार या लाइसेंसधारी द्वारा किया जाना है जिसे खनिजों की खुदाई का अधिकार दिया गया है,

याचिकाकर्ता एक ठेकेदार होने के नाते, कोई खनन कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए उसे रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया जा सकता है-प्रतिवादी ने तर्क दिया कि हालांकि रॉयल्टी का भुगतान पट्टेदार/लाइसेंसधारी द्वारा किया जाना है जिसे खनन किया जाता है

हालांकि, अवैध रूप से खनन के उपयोग को रोकने के लिए पट्टा दिया जाता है निर्माण कार्यों में खनिज, ठेकेदारों को केवल यह दिखाने की आवश्यकता है कि उनके द्वारा खुले बाजार से खरीदे गए खनिज कानूनी रूप से खनन किए गए खनिज हैं

जिस पर रॉयल्टी का भुगतान किया गया है और इस तरह के प्रमाण पर कोई रॉयल्टी नहीं है बाद में ठेकेदार द्वारा देय होगा-उच्च न्यायालय, आर. एस. शेखावत के मामले में अपने फैसले पर भरोसा करते हुए, अपीलार्थी को कटौती की गई राशि की वापसी के लिए खनन विभाग से संपर्क करने का निर्देश दिया

अपीलार्थी के विधेयक से यह सफलतापूर्वक साबित करने पर कि उपयोग किए गए खनिजों का कानूनी रूप से खनन किया गया था, जिस पर पहले से ही रॉयल्टी का भुगतान किया जा चुका था-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः सरकार द्वारा जारी किए गए परिपत्रों में रॉयल्टी के भुगतान की आवश्यकता होती है

केवल उन खनिजों को ध्यान में रखते हुए जिनका उपयोग ठेकेदारों द्वारा नहीं किया जाता है

रॉयल्टी का भुगतान किया गया था-उन्हें उपयोग किए जाने वाले खनिजों के लिए रॉयल्टी के भुगतान की आवश्यकता नहीं थी, जिस पर पहले से ही एक बार रॉयल्टी का भुगतान किया जा चुका था -

ये परिपत्र यह सुनिश्चित करने के लिए थे कि ठेकेदार खनिजों का उपयोग न करें जो रॉयल्टी का भुगतान नहीं है-अपीलार्थी को उच्च न्यायालय का निर्देश, आर. एस. शेखावत के मामले पर भरोसा करते हुए, खनन विभाग से संपर्क करें पर्याप्त रूप से अपने हितों की रक्षा करता है- हालाँकि, अपीलार्थी को प्रतिवादी नं. 2 - खनन इंजीनियर सबूत दिखा रहा है यह स्थापित करें कि इसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले खनिजों पर रॉयल्टी का भुगतान नियमों के अनुसार किया गया था -

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957। 2 , 3 (ई), 9 (2), 15,23 सी-खान और खनिज।

रॉयल्टी के भुगतान के लिए सरकारी परिपत्रउक्त परिपत्रों को चुनौती दिए बिना इस पत्र को रद्द करना-उच्च न्यायालय ने रिट याचिका-स्वामित्व-आयोजित करने का फैसला कियाः उच्च न्यायालय को निर्णय लेने के बाद ही रिट याचिका पर निर्णय लेना चाहिए था हालाँकि, इस पत्र में केवल रॉयल्टी लागू करने वाले सरकारी परिपत्रों का अनुपालन करने की मांग की गई थी और चूंकि ये परिपत्र थे

अपीलार्थी द्वारा चुनौती नहीं दी गई है, उक्त में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है केवल परिपत्रों के अनुपालन की मांग करने वाला पत्र परिपत्रों को कोई चुनौती नहीं होने के कारण राज्य के पास बचाव करने का कोई

अवसर नहीं था इसकी नीति-सर्वोच्च न्यायालय के लिए सरकारी योजना का निर्णय लेना उचित नहीं है।

न्यायालय ने अपील का निपटारा करते हुए अभिनिर्धारित किया।

1.1 राज्य सरकार द्वारा जारी 26.03.2002 दिनांकित पत्र ने जयपुर नगर निगम के आयुक्त को प्रभावित किया निगम सरकारी परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा खनिज पदार्थों के उपयोग के लिए ठेकेदारों से रॉयल्टी की प्राप्ति की मांग करना। रिट याचिका में अपीलार्थी ने केवल 26.03.2002 दिनांकित पत्र को चुनौती दी थी, लेकिन इसे चुनौती नहीं दी थी पहले जारी किए गए सरकारी परिपत्र जिनकी मांग की गई थी उक्त पत्र का पालन किया। [पैरा 35] [751-ए-बी]

1.2 रिट याचिका में उक्त परिपत्रों को कोई चुनौती नहीं होने के कारण, राज्य के पास अपने उपरोक्त का बचाव करने का कोई अवसर नहीं था ठेकेदारों से रॉयल्टी की प्राप्ति की नीति खनिजों के उपयोग के लिए। इस प्रकार, इस न्यायालय के लिए उपरोक्त सरकारी योजना का निर्णय लेना उचित नहीं है। 26.03.2002 दिनांकित पत्र केवल यह सुनिश्चित करने के लिए एक पत्र है परिपत्रों का अनुपालन जिसके द्वारा रॉयल्टी की मांग की गई थी बरामद, उक्त पत्र में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है। [पैरा 36] [751

2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों की व्याख्या इस अर्थ में की जानी चाहिए कि उन्हें केवल उन खनिजों के संबंध में रॉयल्टी के भुगतान की आवश्यकता होती है जिनका उपयोग राज्य सरकार द्वारा किया गया है। इसका उपयोग किया जाता था जिसके लिए एक बार रॉयल्टी का भुगतान पहले ही किया जा चुका था। राज्य ने केवल यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपरोक्त परिपत्र जारी किए हैं कि ठेकेदार उन खनिजों का उपयोग नहीं करते हैं जिन्हें रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया जाता है। [पैरा 40] [753-डी-ई]

3.1 आर. एस. शेखावत के मामले पर भरोसा करते हुए उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को खनन विभाग से संपर्क करने की अनुमति दी गई उस राशि की वापसी जो बिल से काट ली गई थी यदि यह सफलतापूर्वक साबित होता है कि उपयोग किए गए खनिज खनिज थे जिनके लिए रॉयल्टी का भुगतान पहले ही किया जा चुका था। उपरोक्त निर्देश अपीलार्थी के हितों की पूरी तरह से रक्षा करते हैं। [पैरा 41] [753-एफ]

3.2 हालाँकि, अपीलार्थी को संपर्क करने की स्वतंत्रता दी गई है खनन इंजीनियर, प्रत्यर्थी संख्या 2 एक लिखित अभ्यावेदन द्वारा अपने बिलों या रोकी गई राशि से कटौती की गई राशि का विवरण देते हुए प्रमाण के विवरण के साथ उपयोग किए गए खनिजों के विवरण के साथ

यह स्थापित करने के लिए कि उपयोग किए गए खनिज खनिज थे जिनके लिए रॉयल्टी थी।1986 के नियमों के अनुसार भुगतान किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 2 इस पर विचार कर सकता है प्रतिनिधित्व और, यदि यह पाया जाता है कि अपीलार्थी किसी भी राशि की वापसी का हकदार है, तो उचित परिणामी कार्रवाई हो सकती है लिया गया। [पैरा 42] [753-जी-एच; 754-ए-बी]

आर. एस. शेखावत और अन्य बनाम 1998 का उत्तर प्रदेश राज्य एस. बी. सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 359 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 28.02.2001 पर तय किया गया न्यायालय संदर्भित।

सिविल अपीलीय न्याय निर्णयः सिविल अपील सं. 11259 2016।

जयपुर में राजस्थान जयपुर पीठ के लिए उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के एस. बी. सिविल डब्ल्यू. पी. में 2008 की डी. बी. सिविल विशेष अपील (रिट) संख्या 232 मे 2002 का सं. 3191 में पारित निर्णय और आदेश 17.12.2008 से

संजीव कुमार, वेंकटेश्वर राव अनुमोलु, सलाहकार अपीलार्थी के लिए

हर्षा विनॉय, मिलिंद कुमार, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय अशोक भूषण, जे. के द्वारा पारित किया गया।

1. अनुमति स्वीकृत

2. यह अपील उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर की गई है।

राजस्थान के लिए न्यायिक न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर दिनांक 17.12.2008 2008 की डी. बी. सिविल विशेष अपील सं. 238 में, जिसके निर्णय द्वारा, अपीलार्थी द्वारा निर्णय और आदेश के विरुद्ध दायर सिविल विशेष अपील ज्ञात एकल न्यायाधीश दिनांक 20.02.2007 को खारिज कर दिया गया था। संक्षिप्त तथ्य अपील पर निर्णय लेने के लिए नोट करना आवश्यक हैः अपीलार्थी, एक ठेकेदार, जिसे नगर निगम, जयपुर द्वारा लाइसेंस प्राप्त है अपीलार्थी अपने निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए बजरी, पत्थर, ग्रिट, मोरम आदि का उपयोग करता है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि इसे खुले बाजार से खरीदा गया है जयपुर में।

3. राजस्थान राज्य ने विभिन्न सरकारी आदेश जारी किए हैं। दिनांक 20.02.1994,08.11.1996 और 20.11.1996 जिसके द्वारा निर्माण विभाग के ठेकेदारों के बिलों से खनिजों की रॉयल्टी के लिए 2 प्रतिशत की कटौती की गई थी। राजस्थान राज्य दिनांकित 13.11.2000 आदेश देखें। नई योजना के तहत, कार्य की प्रति निर्माण विभाग द्वारा ठेकेदारों को जारी आदेश जिसमें निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले खनिजों की मात्रा का विवरण होना आवश्यक था खनन अभियंता/सहायक खनन अभियंता के

समक्ष प्रस्तुत किया जाना, जिन्हें खनन कार्य शुरू होने से पहले आवश्यक था।

निर्माण में खनिज के उपयोग के लिए अल्पकालिक अनुमति पत्र जारी करें।

4. एक अन्य सरकारी आदेश दिनांक 03.10.2001 पर जारी किया गया था, जिसके द्वारा निर्देश संख्या। 2 & 4 जैसा कि परिपत्र दिनांक 13.11.2000 में निहित है, संशोधित किया गया था।

5. इसके अलावा, 25.01.2002 पर निर्देश जारी किए गए थे। दिनांकित एक पत्र

26.03.2002 सरकार द्वारा मुख्य कार्यकारी को जारी किया गया था इंजीनियर, आयुक्त, जयपुर नगर निगम सरकारी आदेश दिनांक 03.10.2001 और 13.11.2000 और अनुरोध करते हुए जयपुर नगर निगम उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकारी आदेश। यह आगे कहा गया था कि नो ड्यूज सर्टिफिकेट तक खनन विभाग द्वारा ठेकेदारों के पक्ष में जारी किया जाता है, ठेकेदारों के अंतिम बिल के खिलाफ भुगतान नहीं किया जाता है ताकि विभाग और राज्य को किसी भी प्रकार का राजस्व नुकसान नहीं हो सकता है। द. अपीलार्थी ने 2002 की रिट याचिका संख्या 3191 के रूप में रिट याचिका दायर की निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थनाः

" ए। आदेश, आदेश या निर्देश के माध्यम से दिनांकित आदेश 26.03.2002 उत्तरदाता सं. 3 द्वारा पारित अनुलग्नक-5 कृपया रद्द कर दिया जाए और अलग कर दिया जाए।बी। रिट आदेश या निर्देश के माध्यम से, प्रत्यर्थियों को याचिकाकर्ताओं से रॉयल्टी एकत्र नहीं करने के लिए रोका जा सकता है। खुले स्थान से बजरी, ग्रिट, पत्थर, मोरम आदि की खरीद बाजार सी। रिट आदेश या निर्देश के माध्यम से, उत्तरदाताओं को दौड़ से रॉयल्टी न लेने के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है और ठेकेदारों यानी याचिकाकर्ताओं के अंतिम बिल जो पहले दिए गए 26.03.2002 डी। किसी भी अन्य उपयुक्त रिट,आदेश या निर्देश जिसके लिए याचिकाकर्ता की परिस्थितियों में हकदार हो सकता है उसके पक्ष में मामला जारी किया जा सकता है।

ई. रिट याचिका की लागत इसके पक्ष में दी जा सकती है याचिकाकर्ता '।

6. अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा किया गया था 20.02.2007 पर विद्वान एकल न्यायाधीश। सीखा एकल न्यायाधीश निपटाया गया

एस. बी. सी. डब्ल्यू. पी. सं. 359 में पूर्व निर्णय के संदर्भ में रिट याचिका

1998, आर एस शेखावत और अन्य बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य ने 28.02.2001 पर निर्णय लिया।

7. विद्वत एकल के निर्णय से व्यथित अपीलार्थी न्यायाधीश दिनांक 20.02.2007 ने 2008 का डी. बी. सी. एस. ए. सं. 211 दायर किया। डिवीजन बेंच ने माना कि विद्वान एकल द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधता नहीं है आर एस शेखावत और अन्य मामलों (सुप्रा) में न्यायाधीश, इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी की रिट याचिका का निपटारा करते हुए ऐसा नहीं किया एक त्रुटि। तदनुसार याचिका खारिज कर दी गई। डी. बी. दिनांकित 17.12.2008 के निर्णय से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने वर्तमान अपील दायर की है।

8. अपील के समर्थन में अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील यह तर्क देता है कि दोनों विद्वान एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खंड पीठ और के पूर्व निर्णय के संदर्भ में रिट याचिका का निपटारा किया है विद्वान एकल न्यायाधीश, आर एस शेखावत और अन्य जिनमें निर्णय में कोई मुद्दा तय नहीं किया गया था। वह आर एस शेखावत मामले में उस फैसले को प्रस्तुत करता है यह इंगित करता है कि न्यायालय ने इसकी शुद्धता या अन्यथा में प्रवेश नहीं किया अधिसूचना दिनांक 22.09.1994

और 03.07.1994 जो इसके तहत थी चुनौती। अदालत ने सरकार द्वारा जारी नई योजना पर ध्यान दिया 13.11.2000 दिनांकित आदेश में अपीलार्थी के अनुरोध पर ध्यान दिया गया है जो कि महत्वपूर्ण है खान विभाग द्वारा जाँच किए जाने का निर्देश दिया जा सकता है जिसके अनुरोध पर रिट याचिका का निपटारा किया गया था।

9. यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त निर्णय ने निर्णय नहीं लिया आगे प्रस्तुत किया कि रॉयल्टी का भुगतान पट्टेदारों द्वारा किया जाना है या जिन लाइसेंसधारियों को खनिजों की खुदाई का अधिकार दिया गया है अर्थात खनन पट्टा या लाइसेंस धारक। अपीलार्थी जो खरीद रहा है खुले बाजार से खनिजों को भुगतान के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है राजघराने से। अपीलार्थी कोई खनन कार्य नहीं कर रहा है ताकि उसे रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए कहा जा सके।

10. प्रस्तुतियों पर विवाद करने वाले राज्य के लिए विद्वान वकील अपीलार्थी के वकील ने प्रस्तुत किया कि राजस्थान राज्य द्वारा अवैध खनन को रोकने के लिए विभिन्न सरकारी आदेश जारी किए गए हैं। रॉयल्टी के भुगतान के बिना खनिजों का उपयोग। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सरकारी आदेश अवैध खनन की जांच के लिए एक तंत्र प्रदान करते हैं और यदि उपयोग किए जाने वाले खनिज खनिज हैं जो रॉयल्टी भुगतान किए गए खनिज हैं, कोई दायित्व नहीं है और सरकार को केवल ऐसे तथ्यों के

सत्यापन की आवश्यकता है अर्थात क्या ठेकेदारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले खनिज रॉयल्टी भुगतान किए गए हैं या नहीं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त तथ्यों के सत्यापन तक भुगतान रोकने का निर्देश केवल यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है कि उपयोग किए जाने वाले खनिज बिना भुगतान के अवैध रूप से खनन किए गए खनिज नहीं हैं राजघराने। उनका कहना है कि विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ द्वारा रिट याचिका का निपटारा करने में कोई त्रुटि नहीं की गई थी। रिट याचिकाकर्ता खनन में सक्षम अधिकारियों से संपर्क करने के लिए यह साबित करने के लिए कि उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी खनिज रॉयल्टी भुगतान किए गए हैं।

11. हमने विद्वान वकील के प्रस्तुत करने पर विचार किया पक्षकारों ने और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

12. संसद ने खान और खनिज अधिनियम बनाए हैं (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957, विकास के लिए और खानों और खनिजों का विनियमन। खानों के विनियमन और खनिजों के विकास पर संघ के नियंत्रण को धारा के आधार पर घोषित किया गया है 1957 का अधिनियम। धारा 3 (ई) 'लघु खनिजों' को परिभाषित करती है जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए हैः

" 3 (ई) '। माइनर मिनरल्स 'का अर्थ है पत्थर, बजरी, साधारण मिट्टी, बालू के अलावा साधारण बालू का निर्माण करना। निर्धारित उद्देश्य, और कोई अन्य खनिज जो केंद्रीय सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक मामूली खनिज होने की घोषणा करें; "

13. अधिनियम की धारा 15 द्वारा राज्य सरकार को लघु खनिजों पर नियम बनाने का अधिकार दिया गया है।

14. धारा 9 (2) खनन पट्टा धारक द्वारा रॉयल्टी के भुगतान का प्रावधान करती है। धारा 9 (2) इस प्रकार हैः

" 9 (2) . इस अधिनियम के प्रारंभ पर या उसके बाद दिए गए खनन पट्टे का धारक किसी भी मामले में रॉयल्टी का भुगतान करेगा। (उसके द्वारा या उसके प्रतिनिधि द्वारा निकाले गए या उपभोग किए गए खनिज, प्रबंधक, कर्मचारी, ठेकेदार या उप-पट्टेदार) पट्टे पर दिए गए व्यक्ति से द्वितीय में निर्दिष्ट समय के लिए दर पर क्षेत् उस खनिज के संबंध में अनुसूची "।

15. 94 के अधिनियम 25 द्वारा कुछ संशोधनों को शामिल किया गया है। 1957 के अधिनियम में। संशोधन द्वारा जोड़ी गई धाराओं में से एक धारा 23 सी है। धारा 23 सी (1) इस प्रकार हैः

अवैध खनन, परिवहन और खनिजों का भंडारणः(1).राज्य सरकार, आधिकारिक में अधिसूचना द्वारा राजपत्र, अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाएँ, इसके साथ जुड़ा हुआ है।

(2).....

16. राजस्थान राज्य ने राजस्थान की खानों और धारा 15 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए खनिज रियायत नियम, 1986। नियम 3 (2) (XX) 'रॉयल्टी' को परिभाषित करता है जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए हैः

" रॉयल्टी का अर्थ है खुदाई, हटाए गए या उपयोग किए गए अयस्क या खनिज के संबंध में सरकार को देय शुल्क। अनुसूची-। में विहित किसी भी भूमि से।

17. नियम 18 उन शर्तों का प्रावधान करता है जिन्हें प्रत्येक खनन पट्टे में शामिल किया जाना है। नियम 18 (1) (बी) के अनुसार, खनन का धारक इन नियमों के प्रारंभ पर या उसके बाद दिया गया पट्टा उसके द्वारा हटाए गए और/या उसके भीतर उपभोग किए गए किसी भी खनिज के संबंध में रॉयल्टी का भुगतान करेगा। अनुसूची । में निर्दिष्ट समय पर पट्टे पर दिया गया क्षेत्र वह खनिज।

18. नियम 48 में इस संबंध में विभिन्न प्रावधान हैं -अनधिकृत काम करना। खनन के संबंध में विभिन्न प्रावधान खनन पट्टे के अनुसार नहीं संचालन को नियंत्रित किया गया है नियम 48 में अवैध रूप से खनन

किए गए खनिजों की जब्ती भी शामिल है और रॉयल्टी और प्रभार्य कर के साथ-साथ चक्रवृद्धि शुल्क की वसूली।

19. उपरोक्त वैधानिक प्रावधान स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि खनन पट्टे या परमिट के अनुसार लघु खनिजों की खुदाई का भुगतान किया जा सकता है। रॉयल्टी और किराया जैसा कि नियमों में निर्धारित है। रॉयल्टी का भुगतान करने का दायित्व उस व्यक्ति पर है जो खनिजों की खुदाई करता है।पट्टा या लाइसेंस।

20. प्रावधानों से यह भी संकेत मिलता है कि रॉयल्टी के भुगतान के बिना अवैध खनन या खनिजों की खुदाई की स्थिति में, नियम सशक्त बनाते हैं। खनिजों की जब्ती, पुनर्प्राप्ति सहित विभिन्न शक्तियों का प्रयोग

21. अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा पहली दलील जो उठाई गई है, वह यह है कि विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ ने ऐसा नहीं किया रिट याचिका में उठाए गए मुद्दों पर विचार करें और मामले का निपटारा करें मुद्दों का निर्णय लिया गया। आर एस शेखावत का फैसला लाया जाता है।अनुलग्नक पी-2 के रूप में दर्ज करें।

22. उपरोक्त निर्णय इंगित करता है कि रिट याचिका में अधिसूचना दिनांक 22.09.1994 और 03.07.1995 जिसके द्वारा 2 प्रतिशत कटौती की गई थी याचिकाकर्ताओं द्वारा लोक निर्माण विभाग और अन्य राज्य विभागों को खनिजों की रॉयल्टी के लिए प्रस्तुत किए गए बिलों को चलाने के तहत

था चुनौती। उस मामले के याचिकाकर्ता सड़कों, भवनों के निर्माण के व्यवसाय में लगे हुए थे और विभिन्न प्रकार के खनिजों का उपयोग कर रहे थे इसे खुले बाजार से खरीदें। हालांकि, जब रिट याचिका सुनवाई के लिए आए, अदालत ने बाद के विकास को देखा जिसके द्वारा उपरोक्त दो अधिसूचनाओं को एक नई योजना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था 13.11.2000 .

23. उस मामले के याचिकाकर्ता ने, बाद के विकास को देखते हुए, दिनांकित अधिसूचना के संबंध में निर्णय के लिए दबाव नहीं डाला 22.04.1994 और 03.07.1994 लेकिन उनके बिलों से काटे गए रॉयल्टी की वापसी के लिए प्रार्थना की। याचिकाकर्ता ने सुझाव दिया कि मामला हो सकता है खान विभाग द्वारा स्वयं जांच की जाए। निर्णय में निम्नलिखित टिप्पणियों पर ध्यान देना उपयोगी हैः

"..... जैसा कि याचिकाकर्ता के वकील और इन सभी रिट याचिकाओं में उपस्थित अन्य वकीलों ने पहले ही कहा है, अब प्रश्न के निर्णय के लिए जोर देना आवश्यक नहीं समझते हैं। इस बारे में कि क्या दिनांकित 22.09.1994 और 03.07.1994 दो अधिसूचनाएं इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कानूनी हैं या नहीं कि 13 नवंबर 2000 को एक नई योजना का उल्लेख किया गया है। लागू किया गया है लेकिन जहां तक लोक निर्माण विभाग और अन्य विभागों द्वारा पहले से की गई कटौती है

खनन विभाग की ओर से, वही 13 नवंबर 2000 तक खनिजों का उपयोग किया गया था निर्माण कार्य या नहीं जो रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया गया था और इस उद्देश्य के लिए याचिकाकर्ताओं के वकील ने स्वयं सुझाव दिया कि मामले की जांच की जाए खान विभाग एक उचित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि क्या इसमें कोई गलत कटौती की गई थी लोक निर्माण विभाग और अन्य द्वारा बिलों को चलान रॉयल्टी की राशि के संबंध में विभाग या नहीं उपयोग किए गए खनिज।

24. इस प्रकार उपरोक्त रिट याचिका का निपटारा स्वतंत्रता देने के लिए किया गया था याचिकाकर्ता को संबंधित के साथ खान विभाग से संपर्क करने के लिए मूल्यांकन के लिए अभिलेख और दावे के लिए स्थिति की व्याख्या करना धनवापसी या समायोजन टिकाऊ है या नहीं।

25. जब रिट याचिका सं। 3191 अपीलार्थी द्वारा दायर 2002 का 20.02.2007 पर विचार के लिए आए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने आर एस शेखावत मामले में निर्णय पर विचार करने के बाद, रिट का निपटारा किया निम्नलिखित निर्देशों के साथ याचिकाः

> " ..... उपरोक्त निर्णय का अवलोकन करने और उस पर विचार करने के बाद मुझे इस मामले पर कोई अन्य दृष्टिकोण रखने के लिए राजी नहीं किया गया है जिसे उपरोक्त में समन्वय पीठ द्वारा लिया गया है निर्णय।

रिट याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता उपरोक्त निर्देश। की गई टिप्पणियाँ और उपरोक्त निर्णय में दिए गए निर्देश भी लागू होंगे। वर्तमान मामले में।

26. डिवीजन बेंच ने भी उपरोक्त फैसले की पुष्टि की।

27. रिट याचिका में की गई प्रार्थनाओं से यह स्पष्ट है कि रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई सैद्धांतिक प्रार्थना खनन अभियंता, खान और खनन विभाग द्वारा जारी डी. ओ. पत्र दिनांक 26.03.2002 को चुनौती थी। जयपुर नगर निगम, जयपुर के आयुक्त को संबोधित भूविज्ञान।

28. आर एस शेखावत मामले में रिट याचिका का निर्णय 28.02.2001 पर किया गया था, जिस तारीख तक 26.03.2002 दिनांकित पत्र अस्तित्व में भी नहीं था। 26.03.2002 दिनांकित पत्र आर एस शेखावत मामले के फैसले के समय के बाद होने के कारण, यह देखना आवश्यक था पत्र की विषय-वस्तु पर विचार करना और उसके बाद निर्णय लेना। इस प्रकार हम पाते हैं

अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील के लिए प्रस्तुत करने में सार कि 26.03.2002 दिनांकित पत्र पर भी पहले गौर करना आवश्यक था।

29. इस प्रकार हम, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, दिनांकित डी. ओ. पत्र 26.03.2002 की सामग्री और अपीलार्थी द्वारा की गई प्रस्तुतियों की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अपील के समर्थन में।

30. प्रस्तुतिकरण जिसे वकील द्वारा दबाया गया है अपीलार्थी यह है कि रॉयल्टी के भुगतान का विचार धारक से किया जाता है लघु खनिज की खुदाई के लिए अनुमति धारक होना चाहिए और कोई खनिज नहीं रॉयल्टी के भुगतान के बिना हटा दिया गया या खुदाई की गई। सभी खनिजों के खनन के लिए रॉयल्टी का भुगतान आवश्यक है।

31. हालाँकि यह ध्यान रखना भी प्रासंगिक है कि जहाँ खनिज है रॉयल्टी के भुगतान के बिना खुदाई/परिवहन/हटाया गया, वहाँ हैं ऐसे खनिजों की जब्ती, रॉयल्टी की वसूली, कर के लिए विशिष्ट प्रावधान यदि ऐसा कोई खनिज पट्टेदार या उनके एजेंटों द्वारा हटाया गया पाया जाता है रॉयल्टी के भुगतान के बिना, कानून में रॉयल्टी और जुर्माना आदि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं।

32. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पहले के सरकारी आदेश दिनांकित थे 22.09.1994 & 03.07.1995 लोक निर्माण विभाग और अन्य राज्यों के ठेकेदारों के चालू बिलों से 2 प्रतिशत कटौती का प्रावधान जिन खनिजों का उपयोग किया जाता था, उनके स्वामित्व के लिए विभाग सड़क आदि के निर्माण में ठेकेदार। उपरोक्त सरकारी आदेशों के तहत प्रदान की गई योजना को बाद में वापस ले लिया गया और एक नई योजना बनाई गई। योजना को सरकारी आदेश दिनांक 13.11.2000 और 03.10.2001 द्वारा लागू किया गया था। सरकारी आदेश 03.10.2001 द्वारा पहले के

निर्देश को संशोधित करना दिनांक 13.11.2000, निम्नलिखित निर्देश दिया गया थाः

" रॉयल्टी की वसूली के लिए मार्गदर्शन से संबंधित सम संख्या वाले परिपत्र दिनांक 13.11.2000 में संशोधन करने बाद सरकारी निर्माण विभाग के ठेकेदारों द्वारा विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाने वाले खनिजों के खिलाफ और उपरोक्त परिपत्र के पैरा 2 और 4 को प्रतिस्थापित करने के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं जारी किया गयाः

" (2) निर्माण विभाग के ठेकेदार द्वारा खनन कार्य शुरू करने से पहले, अल्पकालिक अनुमति पत्र खनन [2016] 11 एस. सी. आर. से निर्माण में उपयोग किए जाने वाले खनिज के लिए। विभाग प्राप्त किया जाएगा और जमा करना होगा इसके लिए निर्धारित शुल्क और विभाग के साथ खन्ना बुक की लागत, लेकिन खनिज की मात्रा पर देय रॉयल्टी की राशि अल्पकालिक लाइसेंस में उल्लिखित ठेकेदार के चालू बिलों में से संबंधित द्वारा कटौती की जाएगी। मात्रा के आधार पर निर्माण विभाग निर्माण में प्रयुक्त खनिज।

(4) निर्माण कार्य पूरा होने पर, पूरा विवरण खनिज की मात्रा, स्रोत खनिज प्राप्त करना और कटौती की गई राशि का विवरण ठेकेदार द्वारा उपयोग किए गए बिल आदि का विधिवत सत्यापन संबंधित निर्माण के कार्यकारी अभियंता विभाग को 15 दिनों के भीतर खनन अभियंता/सहायक खनन अभियंता को प्रस्तुत किया जाएगा और इसके अलावा निर्माण विभाग का एक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें निर्माण में उपयोग किए गए खनिज की मात्रा निर्धारित की गई है। प्रमाणित "।

33. एक और सरकारी आदेश 25.01.2002 पर जारी किया गया था जिसे अनुलग्नक पी-4 के रूप में दर्ज किया गया है जिसके द्वारा कुछ अन्य यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे कि उपयोग किए गए सभी खनिजों के संबंध में रॉयल्टी का भुगतान किया जाए और खनन इंजीनियर को रखने की आवश्यकता हो सभी विवरण और ठेकेदारों को भी अल्पकालिक अनुमति लेनी थी। कार्य क्रम के अनुसार खनिजों के उपयोग के लिए।

34. खनन इंजीनियर द्वारा 26.03.2002 दिनांकित एक पत्र जारी किया गया था। आयुक्त नगर निगम, जयपुर को, जिसके तहत आयुक्त, जयपुर नगर निगम, जयपुर का ध्यान था सर्कुलर दिनांक 13.11.2000,

और आयुक्त को सूचित किया गया कि हालांकि सर्कुलर की जानकारी पहले जयपुर नगर निगम को भेजी गई है, लेकिन रॉयल्टी की राशि प्राप्त नहीं हुई है। जयपुर नगर निगम के आयुक्त से अनुरोध किया गया था कि उपयोग किए गए खनिजों की मात्रा के आधार पर रॉयल्टी भेजने की व्यवस्था ठेकेदार को दिए गए निर्माण कार्य के अनुबंध में समाप्त होने से पहले जयपुर नगर निगम के अधीनस्थ कार्यालय वित्तीय वर्ष।

35. 26.03.2002 दिनांकित पत्र ने जयपुर नगर निगम के आयुक्त को सरकार का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावित किया 13.11.2000 और 03.10.2001 दिनांकित आदेश जो पहले नोट किए गए हैं। रिट याचिका में अपीलार्थी ने केवल दिनांकित पत्र को चुनौती दी है 26.03.2002 लेकिन पहले जारी किए गए सरकारी परिपत्रों को चुनौती नहीं दी है जिसका उक्त पत्र द्वारा अनुपालन करने की मांग की गई थी।

36. राज्य के विद्वान वकील ने अपनी दलीलों में सही कहा है कि चूंकि अपीलार्थी ने राज्य के उपरोक्त दो परिपत्रों को चुनौती नहीं दी थी सरकार जहां खनिजों के उपयोग के लिए ठेकेदारों से रॉयल्टी की प्राप्ति की योजना लागू की गई थी, राज्य के पास कोई अवसर नहीं था पहले के दो परिपत्रों से संबंधित सभी प्रासंगिक तथ्य देने के लिए जिनके द्वारा रॉयल्टी की वसूली की मांग की गई थी। केवल वर्तमान रिट याचिका में प्रार्थना 26.03.2002 दिनांकित पत्र को रद्द करने के लिए है, जो केवल एक पत्र है

जयपुर नगर निगम आयुक्त दिनांकित परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे 13.11.2000 & 03.01.2001 . परिपत्र के लिए कोई चुनौती नहीं है 13.11.2000 & 03.01.2001 रिट याचिका में और राज्य को अपनी उपरोक्त नीति का बचाव करने का कोई अवसर नहीं मिला, इस न्यायालय के लिए उपरोक्त सरकारी योजना का निर्णय लेना उचित नहीं है। द. 26.03.2002 दिनांकित पत्र केवल अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक पत्र है 13.01.2000 और 03.01.2001 दिनांकित परिपत्रों में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है पत्र में कहा गया।

37. प्रतिवादी द्वारा एक जवाबी हलफनामा पहले ही दायर किया जा चुका है। नं. 1 और 2, राजस्थान राज्य और वर्तमान में खनन इंजीनियर अपील करें। जवाबी हलफनामे में राज्य ने यह मामला उठाया है कि रॉयल्टी का भुगतान करने की देनदारियां ठेकेदारों/पट्टा धारकों के पास होती हैं जिन्हें खनन किया जाता है। पट्टा दिया जाता है। यह भी अनुरोध किया जाता है कि यदि खनिजों की खरीद उस कानूनी स्रोत से की गई है जिस पर रॉयल्टी का भुगतान किया गया है, तो बाद में कोई रॉयल्टी देय नहीं है। जवाबी हलफनामे के उप-पैराग्राफ IV में निम्नलिखित कहा गया थाः

> " IV. कि कानून के प्रश्नों के पैरा IV की सामग्री गलत है, गलत सलाह दी गई है और इसलिए अस्वीकार की गई है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि रॉयल्टी का भुगतान करने का दायित्व ठेकेदारों/पट्टे पर देने वालों के पास होताहै। जिन धारकों को खनन पट्टे दिए जाते हैं लेकिन क्रम में बड़े पैमाने पर अवैध खनन और बाद में अवैध रूप से खनन किए गए खनिजों के उपयोग के कारण होने वाले नुकसान को रोकने के लिए। निर्माण कार्य, राजस्थान राज्य के खान विभाग ने समय-समय पर परिपत्र जारी कर आह्वान किया वैध रूप से और कि ऐसे खनिजों की खरीद नहीं की गई है अवैध खनन से यह निर्धारित करने के लिए कि क्या इस पर रॉयल्टी है खनिजों का भुगतान किया गया है। मामले में, खनिजों किया गया है अवैध खनन से विक्रेताओं / ठेकेदार द्वारा खरीदा गया, राज्य को देय रॉयल्टी की वसूली की जा सकती है। उक्त परिपत्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि खनिजों की खरीद कानूनी स्रोतों से की गई है, जिन पर रॉयल्टी का भुगतान किया गया है, तो बाद में कोई रॉयल्टी देय नहीं है। लेकिन ऐसे मामले में अवैध खनन से खनिज खरीदे जाते हैं, फिर रॉयल्टी जिन्हें विक्रेताओं/ठेकेदारों द्वारा हड़प लिया गया है, उन्हें होना चाहिए राज्य को भुगतान करें। इस तरह के परिपत्र में कोई कमजोरी या अवैधता नहीं है जिसका उद्देश्य वैध रूप से

रॉयल्टी एकत्र करना है। राज्य के कारण और जिनका भुगतान नहीं किया गया है।

38. जवाबी हलफनामे में आगे कहा गया है कि मामले में अपीलार्थी खुले बाजार से खनिजों की खरीद की है, अपीलार्थी को यह साबित करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए थे कि निर्माण कार्य में उपयोग किए जाने वाले ऐसे खनिजों को वैध रूप से खरीदा गया था और फिर उन्हें कोई रॉयल्टी नहीं दी जाएगी।ऐसे मामले में ऐसे खनिज पर अपीलार्थी द्वारा राज्य।

39. यह प्रस्तुत किया जाता है कि विभागीय संचार 18.02.2008 और 16.02.2009 के बावजूद अपीलार्थी को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है खुले बाजार से खनिज खरीदने के अभिलेख, अपीलार्थी के पास है

इस तरह की खरीद का कोई भी रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में विफल रहा। पैराग्राफ VIII में निम्नलिखित कहा गया हैः

" VIII. कि संबंधित पैरा सं। आठ गलत हैं और अस्वीकार किए गए हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि परिपत्र के अनुसार

राजस्थान लघु खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 63 के तहत विभाग द्वारा जारी, यह सभी के लिए अनिवार्य है। लोक निर्माण में सूचीबद्ध/पंजीकृत ठेकेदार'अल्पकालिक

अनुमति' प्राप्त करने के लिए ऊपर उद्धृत विभाग निर्माण कार्यों में उपयोग किए जाने वाले खनिज। याचिकाकर्ता ने खुले बाजार से खनिज खरीदे, तो याचिकाकर्ता को संबंधित दस्तावेज पेश करने चाहिए थे यह साबित करने के लिए कि निर्माण कार्यों में उपयोग किए जाने वाले ऐसे खनिज थे वैध रूप से खरीदा गया। हालांकि इसके बावजूद 18.02.2008 दिनांकित विभाग से संचार और 16.02.2009 इस संबंध में, याचिकाकर्ता कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा है जो यह साबित करता है कि खनिजों को खुले बाजार से वैध रूप से खरीदा गया। यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो साबित करता हो इसका अर्थ है और इसलिए याचिकाकर्ता के आचरण से यह स्पष्ट है कि ऐसे खनिज अवैध रूप से खरीदे जाते हैं और अवैध रूप से खरीदे जाते हैं। खनन किया गया "।

40. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों में शामिल हैं - परिपत्र दिनांक 13.11.2000 के साथ-साथ परिपत्र दिनांक 03.10.2001 होना चाहिए इस अर्थ में व्याख्या की गई कि परिपत्र के संबंध में रॉयल्टी के भुगतान की आवश्यकता होती है केवल उन खनिजों के लिए जिनका उपयोग ठेकेदार द्वारा किया गया है जिनके लिए कोई रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया गया था। परिपत्र की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है कि उपयोग

किए जाने वाले खनिजों के लिए रॉयल्टी के भुगतान की आवश्यकता है, जिसके लिए एक बार रॉयल्टी का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। राज्य केवल यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपरोक्त सरकारी आदेश लेकर आया है कि ठेकेदार खनिजों का उपयोग न करें।

जिनका रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया जाता है।

41. आर. एस. शेखावत के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने जैसा कि उल्लेख किया है ऊपर ठेकेदार को खनन विभाग से संपर्क करने की अनुमति दी गई है उस राशि की वापसी के लिए जो बिल से काट ली गई थी यदि वे सफलतापूर्वक साबित करते हैं कि उनके द्वारा उपयोग किए गए खनिज खनिज थे जिनके लिए रॉयल्टी का भुगतान पहले ही किया जा चुका था। उपरोक्त निर्देशों ने स्पष्ट रूप से ठेकेदारों के हितों की रक्षा की और हमारा विचार है कि अपीलार्थी राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी उपरोक्त निर्देशों से हितों की पूरी तरह से रक्षा की जाती है।

42. हालाँकि, हम इसे स्वतंत्रता देना उचित समझते हैं अपीलार्थी अपने बिलों या राशि से कटौती की गई राशि का विवरण देते हुए एक लिखित अभ्यावेदन द्वारा खनन इंजीनियर, प्रत्यर्थी संख्या 2 से संपर्क करे विवरण के साथ ठेकेदारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले खनिजों के विवरण के साथ रोक दिया गया यह स्थापित करने के लिए सबूत कि उपयोग किए जाने वाले खनिज खनिज थे

जिनके लिए रॉयल्टी सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट थी.1986 के नियमों के अनुसार भुगतान किया गया था। खनन इंजीनियर, प्रत्यर्थी संख्या 2 एक उचित और तर्कपूर्ण निर्णय ले सकता है प्रस्तुत करने के तीन महीने प्रतिनिधि कि अपीलार्थी किसी भी कार्रवाई की वापसी का हकदार है, जो की की जा सकती है।

43. दीवानी अपील का निपटारा किया जाता है

नोट - यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री सोहन लाल शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।